other hand, how do you assess their performance? What is the system that you have to assess their performance?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I am very glad that the hon. Member has asked me that question. First of all, I do not know which Information Centres he is talking about, because the ones at the local airports are the responsibility of the concerned State Governments. They have to take the onus of dealing with their State centres and inform the tourists who come to their States. What we have done from the Centre is to link up the international airports and, hence, the circuits that we have developed for information are highly advanced. We have the latest information in place; you can cross-check at any time. We have a way of assessing from the feedback that we get from various tourists as well as the performance output at these levels. I am also happy to inform you that today, at this point in time, if you look at the tourism figures of last year, we are already up and flying.

SHRI LALIT SURI: Sir, tourism in this country is gaining ground and the tourist inflow has been increasing. Yes, we do have these centres. But these centres are not enough to cater to tourists' needs. I would like to ask the hon. Minister whether it is possible to have private agencies to monitor these as long as the Government does not provide proper manning facilities at airports: Also, is there any possibility of giving fast-track clearance at the airports to foreigners who come here for a little fee?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, so far as giving fast-track clearance to a foreign tourist is concerned, we are now starting a paid-service which will facilitate the tourist who asks for special consideration. If you feel that the Government is not good enough or adequate enough to give the kind of information that you require, then, we will keep an open mind to look into private partnerships in this area also, provided you do not ask me questions in Parliament like this.

MR. CHAIRMAN: Question No. 302.

एअर इंडिया द्वारा विमानों का लीज पर लिया जाना

*302. श्री मोती लाल वोरा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एअर इंडिया ने लीज पर विमान लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने विमान लीज पर लिए जाएंगे और कितनी अवधि के लिए;

(घ) ये विमान कितने पुराने हैं और प्रत्येक विमान के लिए एअर इंडिया को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करना पड़ेगा; और

(ङ) इन विमानों को लीज पर लेने से एअर इंडिया की आय में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि होगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) एअर इंडिया ने, सीधी खरीद से नए विमानों के अर्जन के लम्बित रहने के कारण, वृद्धि एवं आधुनिकीकरण के लिए विमानों को अल्पावधिक उपाय के तौर पर ड्राई लीज पर लिया है।

(ग) एअर इंडिया ने नवम्बर, 2004 में डिलीवर किए जाने वाले एक 747-400 विमान के लिए एक करार किया है। एअर इंडिया ने 17 मध्यम क्षमता के लम्बी दूरी वाले (एमसीएलआर) तथा 3 अत्यधिक लम्बी दूरी (यूएलआर) वाले विमानों को ड्राई लीज के लिए भी पेशकशें आमंत्रित की हैं।

(घ) तथा (ङ) ये पैरामीटर प्राप्त हुई तकनीकी व वित्तीय बोलियों की प्रकृति और पेशकशों के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के आकलन पर निर्भर करेंगे।

Leasing of Aircrafts by AI

†*302. SHRI MOTILAL VORA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Air India has taken a decision to take aircrafts on lease;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the number of aircrafts which would be taken on lease and the period thereof;

† Original notice of the question was received in Hindi.

(d) how old are these aircrafts and the amount that will have to be paid by Air India for each aircraft every year; and

(e) the extent to which Air India's earnings will increase every year by taking these aircrafts on lease?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI PRAFUL PATEL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir.

(b) Air India has taken aircraft on dry lease as a short-term measure for growth and modernization, pending acquisition of new aircraft on outright purchase basis.

(c) Air India has entered into an agreement for one 747-400 aircraft to be delivered in November 2004. Air India has also invited offers for the dry lease of 17 Medium Capacity Long Range (MCLR) and 3 Ultra Long Rang (ULR) Aircraft.

(d) and (e) These parameters would be dependent on the nature of the technical and financial bids received and assessment of the techno-economic evaluation of the offers.

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ड्राई लीज पर कितने विमान लिए गए हैं, उन की शर्तें क्या हैं और ये विमान कितनी अवधि के लिए गए हैं? ...(**व्यवधान**)... यह बता दें, उस के बाद और पूछूंगा। I have put the first supplementary. Let the Minister reply. I will ask the second supplementary after the reply.

श्री प्रफुल्ल पटेल: माननीय सभापति जी, एयर इंडिया के हमारे वर्तमान जहाजों की जो संख्या है, वह 33 फंक्शनल एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें से 18 हमारे स्वयं के हैं और लीज एयरक्राफ्ट की जो संख्या माननीय सदस्य ने पूछी है, वह वर्तमान में 15 है। एयर इंडिया एक्सप्रैस, हमारी नई चार्टर सर्विस, जो हम लो कॉस्ट के नाम से शुरू करने जा रहे हैं, इसमें भी आगे आने वाले दिनों में लीज एयरक्राफ्ट लेने की हमारी कोशिश जारी है।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न ''ग'' में उन्होंने कहा कि 17 मध्यम क्षमता के लंबी दूरी वाले तथा 3 अत्यधिक लंबी दूरी वाले विमानों की ड्राई लीज के लिए पेशकश आमंत्रित की गई है। कुल

मिलाकर कितने विमान अभी तक ड्राई लीज पर लिए गए हैं? जो पेशकश की गई है, वह कितने विमानों के लिए की जा रही है तथा इसकी कुल लागत कितनी होगी? माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि नए विमानों को भी खरीदा जाएगा, अगर नए विमानों को खरीदने की उनकी पेशकश है, तो ये जो ड्राई लीज पर विमान लिए जा रहे है, इनका क्या होगा? ये कितनी अवधि के लिए लिए गए हैं?

श्री प्रफुल्ल पटेल: माननीय सभापति जी, जो प्रश्न है, वह अनेक हिस्सों में है, लेकिन मैं माननीय सदस्य के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। एयर इंडिया में कई वर्षों से विमान खरीदने के कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हो पाई है। कई कारणों से इसमें विलंब होता रहा है। इसलिए यह मध्य की परिस्थिति में, किस प्रकार से जहाजों की आवश्यकता की पूर्ति की जाए, इसके लिए एयर इंडिया ने लीज़िंग का प्रोग्राम अनेक वर्षों से शुरू किया हुआ है। लीज करना सबसे अच्छा रास्ता है, ऐसा हम नहीं मानते है। हम जब तक हवाई जहाज नहीं खरीदते हैं और अगर आज हवाई जहाज खरीदने की प्रक्रिया शुरू भी करते हैं, तो इसमें कुछ अवधि लगती है। ऑर्डर देने के पश्चात् भी हवाई जहाज प्राप्त करने के लिए भी कम से कम डेढ़, दो साल का समय और लगने वाला है। इसलिए एयर इंडिया ने अभी पिछले कुछ समय में अपने बोर्ड में एक रेजोल्यूशन लेकर 17 मीडियम कैपेसिटी, लौंग रेंज एयरक्राफ्ट्स और 3 अल्ट्रा लौंग एयरक्राफ्ट्स को, इस प्रकार से लीज पर लेने की पेशकश की है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है। शायद यह टेंडर कल ही एयर इंडिया को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसकी अधिक जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा कि किन शर्तों पर वे मिलने वाले हैं। लेकिन यह जो एयर इंडिया का पूरा लीजिंग प्रोग्राम है, एयर इंडिया की एक्सपेंजिशन के पूर्व की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए एयर इंडिया ने यह प्रोग्राम स्वीकार किया है, यह निश्चित रूप से अगले दो साल में हो सकती है। जितने टेंडर किए हैं, इसमें कितने एयरक्राफ्ट मिलते हैं, किन दरों पर मिलते है, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को देना मेरे लिए शायद आज संभव नहीं होगा।

श्री संजय निरुपम: आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया एक अरसे से विमान खरीदने की तैयारी में लगा हुआ है। वह हमेशा से विमान खरीदना चाहता है, लेकिन पता नहीं इस देश में और सरकार में प्रकारान्तर से कौन-सी ताकतें हैं जो एयर इंडिया को विमान नहीं खरीदने देती हैं और अंतत: उन्हें लीज़ पर लेना पड़ता है। इस बार माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हम विमान लीज़ पर लेने जा रहे हैं, उस लीज से जुड़ा हुआ एक प्रावधान बजट में है। प्रावधान यह है कि आने वाले दिनों में कोई भी एयरलाइन्स अगर लीज पर एयरक्राफ्ट लेती है तो उस पर दस से पंद्रह परसेंट के आस-पास एडीशनल सेस लगाया जाएगा। इसमें वेस्टिड इंट्रेस्ट क्या है, यह तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जानते होंगे, मुझे उनसे नहीं पूछना है। मैं वेस्टिड इंट्रेस्ट की बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस देश में एक प्राइवेट एयरलाइन्स छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी एयरलाइन्स सिर्फ लीज़ पर

एयरक्राफ्ट लेती है। सिर्फ एक ही एयरलाइन्स खरीदती है और उसे इस सेस से कोई नुकसान नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर आपके सामने बैठे हैं, आपकी सरकार में हैं, आप एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के मिनिस्टर हैं, क्या आपने एक बार भी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा कि आप जो लीज पर यह एडीशनल सेस लगा रहे हैं इससे और कुछ नहीं एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को नुकसान होगा। आपसे इस सवाल के आखिरी हिस्से में पूछा गया है कि लीज पर जो नए विमान लिए जाएंगे, उनसे आय की कितनी वृद्धि होगी। इस संदर्भ में, इस एडीशनल सेस के वातावरण में, क्या माननीय मंत्री जी कुछ आइडिया दे सकते हैं कि एयर इंडिया पर नए लीज रेट कितने आएंगे?

श्री प्रफुल्ल पटेल: आदरणीय सभापति जी, मुझे खुशी है कि सदन में कम से कम हमारे माननीय निरुपम जी ने एक ऐसा प्रश्न रखा है, जो मैं समझता हूं कि न केवल यह हमारे मंत्रालय के लिए एक महत्व का है बल्कि सारे देश के लिए महत्व का है। वर्ष 1989 में आखिरी हवाई जहाज इंडियन एअरलाइन के लिए खरीदा गया था, जब राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे। उसके पश्चात्, निरुपम जी जिस सरकार के अंग थे, साढ़े छह साल में कई बार प्रक्रिया को जरूर शुरू किया गया, लेकिन वह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। आप उनके प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैंने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की, मैंने सिर्फ कहा कि जिस प्रक्रिया को आप कह रहे हैं, उस प्रक्रिया को वहां पर भी पूरा नहीं किया गया। एअर-इंडिया का आखिरी विमान 1996 में आया, वह भी एक विमान आया, मतलब आप सोचिए, इतने बड़े भारी देश में हमारे पास एअर-इंडिया, जो हमारा इंटरनेशनल कैरियर है, उसके पास सिर्फ 33 हवाई जहाज हैं और उसमें से भी हवाई जहाजों की जो उम्र है वह इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोगों को उसके बारे में भी जल्द से जल्द जरा सोचना चाहिए। आज कंपटीटिव जमाना है और इस कंपटीशन के युग में अगर हम अच्छा प्रोडक्ट ऑफर नहीं करेंगे तो कोई हमारी सेवाओं का लाभ लेने वाला नहीं होगा और न टुरिज्म बढ़ेगा। कई बातें हैं, आपने अपने प्रश्न में अलग-अलग तरीके से पूछा है। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक लीज का सवाल है, इस देश में कोई भी एअरलाइन ऐसी नहीं है, इन्क्ल्युडिंग प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जिसके पास लीज के हवाई जहाज न हों।

श्री संजय निरुपम: चेयरमैन साहब।

श्री सभापति: नहीं, मैं एलाऊ नहीं करुंगा। आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: मैंने पूछा लीज का, लीज कितने तरह की होती है?

श्री सभापति: मिस्टर निरुपम, आप बैठ जाइए। मैं एलाऊ नहीं करुंगा। ...(व्यवधान)... यह गलत बात है, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... न, न, यह गलत बात है। ...(व्यवधान)... Let him speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: You will have to listen to me. Otherwise...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: If you want an answer, you will have to listen to me. ...*(Interruptions)*... Otherwise it will go on endlessly.

श्री संजय निरुपम: लीज के प्रकार? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... मैं एलाऊ क्यों करुंगा? मैंने आपको क्वैश्चन एलाऊ कर दिया था।

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I had no hesitation in telling you the factual situation that there are two types of leasing programmes, out of which wet lease and dry lease in India ...*(Interruptions)*... All Airlines ....*(Interruptions)*...

श्री संजय निरुपम: सर, इसमें फाइनेन्स इन्वोल्व है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

SHRI PRAFUL PATEL: How are you and me are concerned with the leasing programmes of the companies? It is not my business to run the business of others. ...*(Interruptions)*... You want information; I am giving you the information. If you do not want, I have no issue. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Nirupam, I am not going to allow you. ...*(Interruptions)*... Shrimati Najma Heptulla. ...*(Interruptions)*... I am not going to allow. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... This is not fun. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: The answer is very important. ...*(Interruptions)*... Let the Minister complete his answer. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: यही तो कह रहा हूं, लेकिन वह कंपलीट नहीं करने दे रहे।

SHRI PRAFUL PATEL: I am trying to answer this not because only you raised it. I think it is important for the whole House and the whole country to be able to understand what is happening and we should find a solution. There is no point in being critical. We have been here only for

three months. Do try to be critical of something, which has been a historical problem. Therefore, you should be at least kind enough to understand that if this sector has to be revived and improved, there has to be a sustained effort....*(Interruptions)*...

श्री संजय निरुपम: सर, गलत इंफारमेशन दे रहे हैं, कैसे अंडरस्टैंड करूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप बोल क्या रहे हैं? आपको जवाब नहीं मिलेगा, इस पर। आप बैठ जाइए।

SHRI PRAFUL PATEL: You are raising a question which is not helping in any way, in trying to find a solution... *(Interruptions)*... We are at all. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: The answer is very important. ...*(Interruptions)*... Let the Minister complete his answer. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: The Civil Aviation Ministry, Sir, is seized of the matter. We have made a representation on behalf of the Ministry to the hon. Finance Minister. His viewpoint is also there. I am sure, he will address it in his own way. I do not wish to enter his domain. At the same time, we as the Civil Aviation Ministry, as I mentioned in the earlier part of the question, have no other choice but to go in for leasing as a short-term solution to bridge the gap between what we have and what is the expected demand in the near future.

With this in mind, we have already made a representation on the point which you have just raised on the lease withholding tax. The Finance Ministry also has its own views. Therefore, my only answer to the point you have raised here is, yes, leasing is a short-term solution and it is being adopted by all the airlines, including the private and public in the country, to meet the short-term requirements of the airlines.

डॉ० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: थैंक्यू मंत्री जी। आपने जो जवाब दिया है कुछ सुनाई दिया है, कुछ हंगामें में सुनाई नहीं दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री प्रफुल्ल पटेल: वह महाराष्ट्र की राजनीति है। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, महाराष्ट्र की राजनीति का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नजमा जी, पहली बार क्वेश्चन कर रही हैं, उन्हें क्वेश्चन करने दीजिए। ...(व्यवधान)...

डॉ॰ (श्रीमती) नजमा ए॰ हेपतुल्ला: सर, मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से बाहर हूं। आपके महाराष्ट्र के झगड़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी मुझे राष्ट्र के बारे में पूछना है। ...(व्यवधान)..आप मुझे सवाल पूछने दीजिए।...(व्यवधान)... मंत्री जी, आपने विस्तार से जवाब देने की कोशिश की है। मुझे आपसे दो चीजें पूछनी हैं। एक तो जो आप लीज पर एयरक्राफ्ट्स ले रहे हैं, इसका एक्सचेकर पर कितना बर्डन पड़ने वाला है? दूसरा प्रश्न यह है कि इतने वर्षों से एयरक्राफ्ट्स नहीं खरीदे गये, चाहे कोई भी सरकार थी उसने नहीं खरीदे, क्या आप इस हाउस को कांफीडेंस में लेंगे कि क्यों एयरक्राफ्ट नहीं खरीदे गये? उसके पीछे क्या वजह थी? आपके मंत्रालय ने और आपने स्वयं कोशिश की होंगी या आपसे पहले जो मंत्री रहे हैं उन्होंने इस बारे में कोई कोशिश की होगी। क्या आपने इसकी जानकारी ली कि क्यों इतने सालों से एयरक्राफ्ट्स नहीं लिए और वैट लीज और ड्राई लीज लेने की वजह से देश का फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान कितना हुआ है?

श्री प्रफुल्ल पटेल: आप राजस्थान से हैं इसलिए आपका और हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपका राजस्थान के रहने वाले किसी से भी झगड़ा नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने ...(व्यवधान)...

श्री बलवीर के॰ पुंज: अगर राजस्थान वालों से कोई झगड़ा नहीं है तो किससे झगड़ा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: उनका किसी से झगड़ा नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति महोदय, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसीलिए मैंने बड़ी गंभीरता से इस प्रश्न का उत्तर देने की पहले कोशिश की थी। मैंने सदन में यही कहा है कि यह प्रश्न पूरे देश का है। यह कोई हमारे अकेले मंत्रालय का नहीं है। आपने पूछा है कि लीज़ टैक्स का कितना बोझा एयरलाइंस पर आयेगा। इसके बारे में मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि पहली बात तो यह Lease withholding tax is effective from 1st September, 2004 onwards हम आगे कौन से हवाई जहाज, कितनी संख्या में लेंगे, उसकी कितनी लीज का टैक्स असर होगा, यह क्वेंटीफाई करना आज मेरे लिए शायद संभव नहीं होगा। आगे होने वाली लीज प्रोग्राम के ऊपर कितने हवाई जहाज आते हैं, उसके बाद ही मैं उसको क्वेंटीफाई कर सकूंगा। It will not be possible for me to given you because the lease comes

from rich countries. There is a DTA between country to country. I cannot at this juncture, without any details, tell you which aircraft are going to be leased, when and from whom. As I said, the tenders have only come in yesterday. It will not be possible for me to quantify about anything on this issue. If there is any information, as and when I receive it, I will pass it on to the hon. Member. I will assure that. As far as acquisition of aircraft is concerned, I can assure you that what has happened in the past will not be repeated in the future. At least as far as we are concerned, we are very committed.

We have asked both the airlines to come up with their programmes at the earliest. There has been an issue ....(*Interruptions*)... I would, Mr. Chairman, with your protection, like to inform the House that earlier the acquisition programmes were based on the requirements of 1998. After 1998, the Boards passed resolutions. We are now in 2004. The aviation industry worldwide and in our country has undergone a change. The needs of Indian Airlines and the Air India have undergone a change. Some of the aircraft, which were owned by the Indian Airlines and the Air India, were acquired in 1998. We are not in 2004 and some of them are going to be phased out, or, have already been phased out, or some of them have become obsolete. As you have rightly said that the average age of an aircraft in India is the highest in the world. So, with this in mind. we have asked Indian Airlines and Air India to quickly come out with a new programme. As soon as we are ready, we will assess the issue; and further progress on that will take place.

पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास के बारे में सम्मेलन

*303. **श्री हरीश रावत:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचायती राज व ग्रामीण विकास के बारे में हाल ही में दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों एवं पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्रियों के सम्मेलन की मुख्य सिफारिश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।